अव्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े करती निष्पक्ष,निर्भीक खबरों का दैनिक संकलन

Daily NEWS ALERT

खबरों पर सरकार का पक्ष जानने के लिए लॉगिन करें:-
www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

01 2020/dna/jpr/04 जयपुर संस्करण E-News-Digest, Issued in Public Interest सोमवार, 27 अप्रैल 2020

हिंडौन के सर्वे में खुलासा • दूसरे चरण में किसी को आधा तो किसी के हाथ ही नहीं आया राशन किट

2720 जरूरतमंदों की सूची में 468 संपन्न लोगों के नाम, सभी के घर पहुंचा गरीबों का राशन

कासं | हिंडौन सिटी

• प्रशासन ने तीसरे चरण के तहत राशन सामग्री का वितरण करने से पहले कराया था सर्वे

• अब अपात्रों के नाम हटाकर पात्र 1014 लोगों के नाम जोड़े

• तीसरे चरण में 28 अप्रैल से 3266 गरीब परिवारों को मिलेंगे अब राशन के किट

कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। इसके बावजूद हिंडौन शहर में पार्षदों के माध्यम से जरुरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए गए नामों में कई संपन्न लोग भी शामिल हो गए।

ऐसे में प्रथम एवं दूसरे चरण में जिन 2720 जरुरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाई गई, उनमें 468 अपात्र लोग भी शामिल रहे। यह खुलासा कलेक्टर के निर्देश पर तीसरे चरण के तहत वितरित की जाने वाली राशन सामग्री से पहले कराए गए सर्वे में हुआ है। यही नहीं दूसरे चरण में कई असली गरीबों को आधी तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। सर्वे के बाद 468 अपात्र लोगों के नाम हटाने की अभिशंषा के साथ 1014 गरीबों के नाम जोडे गए हैं। ऐसे में अब 28 अप्रैल से वितरित की जाने वाली राशन सामग्री में 3266 गरीब परिवार लाभांवित हो सकेंगे। कलेक्टर के निर्देश पर वार्ड वाइज इंसीडेंट कमांडर,बीएलओ,महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे किया गया था।

झूठी शिकायत हुई तो होगी कार्रवाई

एसडीएम सुरेश कुमार यादव ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का लाभार्थी की सूची में नाम होने के बाद अगर दोनों चरणों का राशन नहीं दिया गया है तो गंभीर मामला है। यदि किसी ने राशन नहीं मिलने की झूठी शिकायत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आरोप गलत है

इस मामले में वितरण प्रभारी नगरपरिषद के नगर नियोजक विनोद शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि इन लोगो को दोनों चरणों का पूरा राशन दिया गया है। इनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है।

पहले चरण में 10 किलो आटा व घरेलू सामग्री, दूसरे चरण में 20 किलो गेहूं व 5 किलो चावल का वितरण

नगरपरिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी में रोजाना कमाकर पेट भरने वाले असहाय गरीब और जरूरतमंदों को जिला प्रशासन की ओर से नगरपरिषद के कार्मिकों द्वारा दो चरणों मे राशन सामग्री का वितरण किया गया था। पहले चरण में 10 किलो आटा और घरेलू सामग्री दी गई और दूसरे चरण में मिड डे मील के तहत 20 किलो गेहू और 5 किलो चावल दिया गया। जिन लोगो को यह सामग्री दी गई उनकी 2720 की लिस्ट थी।

कांग्रेसी सहन

रेणु सैन

इन गरीबों ने लगाया आरोप

मंडावरा रोड पर एक किराए के मकान में रह रहे मूलतः बिहार निवासी लल्लन सहन व कांग्रेसी ने बताया कि वे कई वर्षों से यहाँ रहकर मजदूरी करते हैं और लॉकडाउन के चलते ना तो मजदूरी मिली ओर ना ही बिहार जा पाए। ऐसे में इधर-उधर से खाना मांगकर पेट भरने लगे। चार दिन पहले प्रशासन के लोग आए और 3-4 किलो चावल की थैली दी। जबकि लल्लन व कांग्रेसी का लाभार्थियों की सूची में 264 व 266 नम्बर पर नाम भी अंकित था तो ऐसे में इनको दोनों चरणो का राशन मिलना चाहिए था।

झाड़ू पौछा कर बच्चों का पेट भरती हूं : रेणु सैन

इसी प्रकार मंडावरा फाटक के पास प्रजापति कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली बेवा रेणु सैन ने बताई की उसके पति की मौत हो चुकी है और हम चार लोग है। मैं घरों में झाड़ पौछा कर बच्चों का पेट भरती हूं। मुझे केवल एक चरण में मिलने वाला 10 किलो आटा व राशन सामग्री दी गई और दूसरे चरण के 20 किलो गेहू व 5 किलो चावल नहीं दिए गए। जबकि रेणु सैन का लाभार्थियों की सूची में 303 पर नाम अंकित है।

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-दैनिक भास्कर,करौली	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन,करौली	संबन्धित मामला:-हेराफेरी,मिलीभगत,राहतकार्यों मे भेदभाव

02

तीन की बजाए मिला एक माह का अनुदान, चिकित्सकों की कमी से नहीं मिल रहा उपचार

गोशालाओं को समय पर नहीं सरकारी मदद

छबड़ा. कस्बे सहित क्षेत्रमें सरकारी अनुदान पर दो गौशालाएं संचालित हैं। छबड़ा-धरनावदा मार्ग पर हनुवतखेड़ा में वर्ष 2016 से चारागाह भूमि पर शुरू हुई श्रीबालाजी गोशाला में वर्तमान में 250 गाये हैं, लेकिन समिति के सदस्य सरकारी सहयोग पूरा न मिलने से परेशान है। समिति के अध्यक्ष बनवारी मालव, सचिव मनीष मालव ने बताया कि गत वर्ष से ही अनुदान मिलने लगा है, लेकिन यह अनुदान इस गोशाला की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। चारागाह भूमि पर संचालित इस गोशाला के जमीन आवंटन के लिए गत वर्ष जिला कलक्टर के यहां हुई बैठक में भूमि आवंटन के लिए फाइल दे रखी है, जिसका आवंटन अभी तक नहीं किया। जगह की कमी के कारण चारागाह भूमि पर गायों को रखने के लिए निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा। गौशाला के पास ऐसा कोई भवन भी नहीं है जहां बरसात के समय इन गायों को सुरक्षित रखा जा सके। चारा भंडारण के लिए चद्दर नुमा भुसाघर बनाया गया है। उसमें पूरे वर्ष का चारा रखने की जगह न होने के कारण चारा खुले में पड़ा रहता है और बरसात के बाद गायों के चारे की समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। समिति के अध्यक्ष हरिओम मालव के अनुसार हमारे पास 500 गाय रखने की क्षमता है। लेकिन सरकारी अनुदान एवं गायों को रखने के लिए भूमि का आवंटन, पक्का भवन, भूसाघर निर्माण का पैसा मिले तो हम रोड पर घूमने वाली अन्य गायों की भी व्यवस्था कर सकते हैं।

छबड़ा क्षेत्र के हनुमत खेड़ा स्थित श्री बालाजी गौशाला में पानी पीती गाये। पत्रिका

अटरू के गोविन्दपुरा गांव में संचालित गौशाला में मौजूद गाये। पत्रिका

खलती है चिकित्सकों की कमी

कस्बे के धरनावदा मार्ग कटखंडी मंदिर के पास संचालित श्री गोवर्धन संवर्धन गोशाला के अध्यक्ष मनोज राठौर ने बताया कि नगर पालिका द्वारा वर्ष 2017 के बाद से ही गौशाला के गायों के चारे के लिए अनुदान देना बंद कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2019 से राज्य सरकार से गायों के चारे का अनुदान मिलना शुरू हुआ। समिति के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पशु चिकित्सकों की कमी होना है। सरकार से मिलने वाला अनुदान जो पिछले वर्ष ही शुरू हुआ है अगर समय पर मिले तो गायों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। समिति के कोषाध्यक्ष चेतन सोनी ने सरकार से गायों को मिलने वाले अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की। श्रीगोवर्धन संवर्धन गोशाला में 300 गायों के रखने की व्यवस्था है लेकिन ग्रामीण इलाके से काफी गायों के कस्बे में आने के बाद इन गायों को गोशाला में रखने का दबाव समिति के सदस्यों को सहना पड़ता है। जिसके लिए समिति के सदस्यों ने सरकार से अतिरिक्त अनुदान की मांग की है

नहीं हुआ सेनेटाइजेशन

दोनों ही अनुदानित गौशालाओं में महामारी कोरोना वायरस के बाद अभी तक प्रशासन द्वारा सेनेटाइजेशन नहीं कराया गया है। समिति के सदस्यों ने प्रशासन से गौशालाओं में सेनेटाइजेशन करवाने की मांग की।

सरकारी अनुदान राशि बढ़ाई जाए

अटरू. कस्बे के गोविन्दपुरा में संचालित नन्दनी गौशाला में राज्य सरकार से 12 माह के स्थान पर छह महीने के चारे के लिए आने वाली राशि का भुगतान हर बार तीन-तीन महिने का आता है। लेकिन इस बार एक महिने का ही भुगतान आया है। उसके बाद भी गौशाला में मौजूद 250 गोवंश के लिए चारे की कमी नहीं है। इस वर्ष भी तीन सौ बीट चारा लिया गया है। गौशाला के लिए जनसहयोग भी मिलता है। कोरोना वायरस के चलते अभी तक यहां रहने वाले गौवंश की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। गौशाला समिति के सदस्य मनीष राठौर ने बताया कि यहां करीब चार-पांच बीघा चरागाह भूमि पर तार फेंसिंग कर गौवंश को रखा हुआ है। संक्रमण के चलते गौवंश को बाहर नहीं निकलने देते। समिति के सदस्यों ने राज्य सरकार से 6 के स्थान पर 9 महीने का अनुदान देने व सरकार से अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की है, ताकि चारे के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी की जा सके।

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-राजस्थान पत्रिका,छबड़ा	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन,छबड़ा(बारां)	संबन्धित मामला:-अव्यवस्था

03

ग्रामीणों ने की राशन डीलर को हटाने की मांग

परतापुर| गढ़ी उपखंड के डडूका भाग द्वितीय के राशन डीलर को हटाने द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी करने की शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम रामचंद्र खटिक से की है। साथ ही राशन वितरण की व्यवस्था लैम्पस के जरिए कराने की मांग की है। गांव के सज्जनसिंह झाला, योगेश, ममता, हरिशंकर आदि ने बताया कि डडूका की राशन डीलर विनबाला जैन है, संचालन अशोक जैन करता है। जो राशन का गेहूं लोगों को नहीं देता है और गाली गलौच करता है। शिकायत दो दिन पहले एसडीएम को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता में परमेश, कमलेश, वैदिक, हीरालाल, कचरू उपस्थित थे।

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-दैनिक भास्कर,बांसवाड़ा	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन बांसवाड़ा	संबन्धित मामला:-अव्यवस्था,हेराफेरी

04

सरकारी कर्मचारियों से होगी गेहूं की वसूली, करेंगे कार्यवाही

राजस्थान पत्रिका
खबर का असर

चितलवाना. दूठवा पंचायत के गांवों में लगे सरकारी कर्मचारियों के नाम से खाद्य सुरक्षा के गेहूं उठाने के मामले में एसडीएम ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। एसडीएम के निर्देश पर इन कर्मचारियों की ओर से तीन साल में उठाए गए करीब एक टन गेहूं की वसूली की जाएगी। साथ ही दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी। गौरतलब है कि दूठवा पंचायत के बड़सल की बेरी निवासी शिक्षक राजूराम व टीकमाराम के नाम से पिछले तीन साल से खाद्य सुरक्षा के करीब एक टन गेहूं उठाए गए थे। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से गरीबों के गेहूं की वसूली करने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

कई कर्मचारियों के नाम की संभावना

पंचायत समिति के कई गरीब पात्र लोगों ने कलक्टर से खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं होने की शिकायत की थी। जिसके बाद कलक्टर की ओर से पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन कर जांच करवाई जा रही है। ऐसे में और भी कई सरकारी कर्मचारियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने की संभावना है।

इनका कहना है

पंचायत समिति क्षेत्र में और भी कई सरकारी कर्मचारियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े होने की संभावना है। रिपोर्ट सामने आने पर ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। वैसे इन दोनों कर्मचारियों से गेहूं की वसूली के साथ उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

- मासिंगाराम जागिड़, एसडीएम चितलवाना

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-राज. पत्रिका,जालोर
प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन,जालोर
संबन्धित मामला:-हेराफेरी,गबन

05

क्या-क्या रंग दिखाएगा कोरोना: कड़ी धूप में 10 किमी पैदल चलकर खेतों से चुनकर लाती हैं बालियां, तब कहीं जलता है घर में चूल्हा

लॉकडाउन में बदली जिंदगी...कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट

बूंदी. लॉकडाउन में रोजी का ठिकाना नहीं रहा और राहत का राशन भी अब मिलना कम हो गया तो शहर के गरीब परिवारों के सामने सुबह-शाम रोटी का संकट खड़ा हो गया।

शहर के गरीब परिवारों की महिलाओं ने घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए गांवों में खेतों की ओर रुख कर लिया। रोज सुबह घर का काम निबटा कर शहर के गरीब परिवारों की ये महिलाएं 10-12 किमी पैदल चलकर खेतों में जाती हैं। फसल कटाई के बाद खेतों में पड़ी रह गई गेहूं की बालियां एक-एक कर चुनती हैं। सुबह आठ-नौ बजे से खेतों में बालियां चुनना शुरू करती हैं। कड़ी धूप और सात-आठ घंटे खेतों में भटकने के बाद हर महिला तीन से चार किलो गेहूं जमा करती हैं। शाम चार बजे घर लौटती हैं। बालियों से गेहूं के दाने अलग करती हैं, घट्टी से पीसती हैं तब कहीं शाम का चूल्हा जलता है और परिवार को दो वक्त की रोटी मयस्सर होती है। लॉकडाउन ने गरीब हो या अमीर, हर किसी की जिंदगी को प्रभावित किया है। इसने जरूरतमंद परिवारों को पुश्तैनी धंधा भी बदलने पर मजबूर कर दिया है। जो हाथ चूड़ियां बनाते थे, वे सब्जी के ठेले लगा रहे हैं।

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-दैनिक भास्कर,बूंदी	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन,बूंदी	संबन्धित मामला:-बेरोजगारी,भुखमरी

06

चिंता • जुलाई तक देखरेख की नहीं होने की वजह से यह डर, प्रशासन ने मांगी सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों सूचना

सरकारी स्कूलों में पोषाहार का 30 हजार क्विंटल अनाज खराब होने की आशंका...क्योंकि स्कूल जुलाई में खुलेंगे

भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने 13 मार्च से स्कूलों में बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया था। तब से स्कूलों में पोषाहार वितरण बंद है। इसके बाद 22 मार्च से लॉक डाउन की घोषणा हो गई। सभी स्कूलों में भी पूर्ण अवकाश हो गया। जिले की 2911 उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा के 2.73 लाख छात्र-छात्राओं को मध्यान भोजन दिया जा रहा था। मध्यान भोजन के लिए स्कूलों में वर्तमान में 22 हजार क्विंटल गेहूं और 8 हजार क्विंटल चावल पड़ा है। लगातार देखरेख नहीं होने से खराब होने लगा है। तीन मई तक लॉक डाउन है। 15 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। ऐस में संभावना है एक जुलाई से पहले विद्यालय संचालित नहीं होंगे। ऐसे में चार माह तक अनाज बच्चों के उपयोग में लेने लायक नहीं रहेगा। स्कूलों में उपलब्ध अनाज सरकारी स्कूलों तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति में 21844 क्विंटल गेहूं तथा 8089 क्विंटल चावल पड़ा है। सबसे ज्यादा 4414 क्विंटल अनाज आसींद ब्लॉक, बनेड़ा में 1298, बिजोलिया में 1850, हुरडा में 2202, जहाजपुर में 3646, कोटडी में 1274, मांडल में 2769, मांडलगढ़ में 2592, रायपुर में 1032, सहाड़ा में 1754, शाहपुरा में 2993 सुवाणा में 2570 शहर के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन में 1433 क्विंटल अनाज है।

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-दैनिक भास्कर,भीलवाडा	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-शिक्षा विभाग,भीलवाडा	संबन्धित मामला:-पोषाहार वितरण

07

कोरोना साइड इफैक्ट • सिलबट्टे पर आटा पीसने को मजबूर बामनवास कंटेनमेंट जोन के बाशिंदे

कोरोना मरीज मिला तो पूरी बस्ती से अछूतों का बर्ताव, चक्की वाले नहीं पीसते आटा तो दबंग हैंडपंप से नहीं भरने देते पानी

जगदीश छीपा | बामनवास

कोरोना वायरस का संक्रमण और इसके कारण हुआ लॉक डाउन पूरे देशभर के लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। देशभर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं और मरीज मिलते ही उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन के अलावा सख्त कर्फ्यू लगाकर सारी गतिविधियां बिलकुल बंद कर दी जाती हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा ऐसे इलाकों के लोगों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दूध, सब्जी, दवाएं और अन्य जरूरी चीजें लगातार मिलती रहें लेकिन बामनवास की बैरवा बस्ती में कोरोना का मरीज क्या मिला पूरे मोहल्ले के लिए जैसे मरीज मिलना अभिशाप हो गया। हालांकि सावधानी रखी जाए और लॉक डाउन तथा कर्फ्यू का पालन ठीक तरीके से किया जाए तो संक्रमण फैलने की आशंका ना के बराबर है लेकिन प्रशासन और समाज का जो चेहरा यहां मरीज मिलने के बाद सामने आया है वह बेशक शर्मनाक और एक क्रूर सच्चाई से रूबरू कराने वाला है। इस इलाके से लगातार परेशानियों की खबरें मिलने के बाद भास्कर संवाददाता ने हालात से रूबरू होने के लिए कंटेनमेंट जोन का दौरा किया।

इलाका सील करने के बाद भूला प्रशासन

दरअसल कस्बे के डूंगरी वाले हनुमानजी के पास बैरवा बस्ती में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरी तरह सील कर दिया गया। न बाहर के लोग यहां जा सकते ना यहां के लोग बाहर निकल सकते। ऐसे में सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि यहां के लोगों की दैनिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता लेकिन प्रशासन इस इलाके को सील करने के बाद जैसे भूल ही गया। अब यहां के बाशिंदे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इस इलाके में बैरवा जाति के अलावा कुछ परिवार बागरिया जाति के भी रहते हैं। ज्यादातर लोग मजदूरी कर रोज खाने वाले हैं। बस्ती के लिए पानी का एकमात्र स्रोत बस्ती के पास हैंडपंप है लेकिन वहां दबंग इन लोगों को हैंडपंप से पानी नहीं भरने देते, कहते हैं हैंडपंप के हाथ लगाओगे तो यहां भी वायरस का संक्रमण फैल जाएगा।

गेहूं की घूघरी पकाकर खाने की मजबूरी

बात सिर्फ पानी तक ही खत्म नहीं होती, कई परिवारों का आटा खत्म हो गया, जब वे गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पर गए तो चक्की वालों ने उनका गेहूं पीसने से इनकार कर दिया। अब भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी देखिए कि कई परिवार तो सिलबट्टे पर ही गेहूं को पीसकर इसका आटा बनाते हैं और रोटियां बनाकर परिवार का पेट भरते हैं। वरना घूघरी (गेहूं को पानी में उबालकर पकाया जाने वाला खाद्यान्न) बनाकर खा रहे हैं।

मां बहरी, बेटी गूंगी, दोनों तीन दिन से भूखी

बामनवास | कंटेनमेंट जोन में रहने वाली कंचन देवी और उसकी गूंगी बेटी।

कंचन देवी और उसकी बेटी की दर्दभरी दास्तानः इसी बस्ती की रहने वाली कंचन देवी बहरी हैं और उसकी बेटी गूंगी। सरकारी योजनाओं से मिलने वाले अनाज से किसी तरह दोनों अपना पेट भरती हैं क्योंकि दोनों के अलावा परिवार में कोई नहीं है। अब सरकारी अनाज खत्म हो गया। जब आम दिनों में अनाज नहीं होता है तो पड़ोसी मदद करते हैं लेकिन अब पड़ोसियों के खुद के ही खाने के लाले पड़े हैं तो वहां से भी मदद नहीं मिल पा रही है। मां बेटी ने बताया दोनों तीन दिन से भूखी हैं।

मजदूरी बंद, फाकाकशी की नौबत

लॉक डाउन को एक महीने से ऊपर हो गया, मजदूरी बंद है और ज्यादातर लोग यहां मेहनतकश वर्ग के हैं। केदार बागरिया बताते हैं एक महीने से घर बैठे खा रहे हैं, अब जमा पैसा खत्म हो गया तो फाकाकशी की नौबत आ गई है। केदार के परिवार में 10 सदस्य हैं, चिंता यह है कि अनाज खत्म हो गया है, अब परिवार का पेट कैसे पालेंगे। किसी तरह गूंगे बहरे हो चुके प्रशासन तक इन गरीबों की पुकार पहुंचे और यहां व्यवस्थाएं सुधरें तो ठीक होगा वरना कोरोना से तो नहीं लेकिन इन लोगों की जिंदगी मुसीबतों से ज्यादा दूभर हो जाएगी।

चक्की वाला भी आटा पीसेगा. हैंडपंप से पानी भी भरेंगे

बस्ती के लोगों की कुछ समस्याएं सामने आई थी। चक्की वालों को गेहूं पीसने के लिए पाबंद किया गया है, हैंडपंप से भी पानी भरने से इन लोगों को नहीं रोका जाएगा। खाने पीने के सामान की ग्राम पंचायत के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है।

हेमराज परिडवाल, उपखंड अधिकारी, बामनवास

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-दैनिक भास्कर,गंगापुर सिटी	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन,गंगापुर सिटी	संबन्धित मामला:-बेरोजगारी,भुखमरी,भेदभाव

08

खींवसर उपखंड मुख्यालय पर राशन डीलरों द्वारा लोगों का केरोसिन हड़पने का मामला, लोगों ने शिकायत की तो उसे वापस लेने का दबाव बनाकर धमकाया भी

राशन डीलर ने अवैध रूप से उठाया केरोसिन, शिकायत की तो फोन पर दी धमकी

भास्कर संवाददाता | नागौर

लॉकडाउन में लोग जरूरतमदों तक सामग्री पहुंचा रहे हैं। मगर कुछ लोग भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे है। ऐसा ही एक मामला खींवसर मुख्यालय पर सामने आया है। सरकार द्वारा भले ही जरूरतमंदों व गरीब लोगों को फ्री में राशन देने की घोषणा की गई हो मगर राशन डीलरों द्वारा लोगों के राशन से मिलने वाली सामग्री हड़पने जैसे कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। यहां राशन डीलरों द्वारा केरोसीन गबन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर पोस मशीन में अंगूठा लगाकर गेहूं दे देता है, लेकिन केरोसिन नहीं देता। केरोसिन खुद उठा कर कालाबाजारी करता हैं। ग्रामीणों द्वारा केरोसिन मांगने पर उन्हें केरोसिन आया ही नहीं कह कर मना कर दिया जाता है। लोगों को उनके साथ हुए छलकपट की जानकारी तब पता चली जब कुछ लोगों ने अपने राशन को ऑनलाइन चेक किया तो उसमें केरोसिन भी उनके नाम पर उठाया हुआ दिखाई दिया। हांलाकि इस पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ऑनलाइन शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं शिकायत के बाद राशन डीलर मामले को दबाने के लिए शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे है। वहीं पीड़ित को धमकी देने का मामला भी सामने आया है। राशन डीलर द्वारा ऐसी गड़बड़ी कर लोगों के साथ धोखा करने को लेकर लोगों ने रोष जताया तथा राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

गड़बड़ी : केरोसीन मांगने पर डीलर बोला-सप्लाई में नहीं आया, ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा तो उनके नाम से उठा मिला केरोसीन

पूर्व में राशन वितरण में आ रही अनियमितताओं को देखते हुए सरकार ने पोस मशीन से वितरण प्रणाली शुरू की है, ताकि कार्डधारक को उसका अंगूठा लगाने के बाद स्वयं को ही राशन सामग्री मिल सके, लेकिन कई राशन डीलरों ने इसमें भी अनियमितता करने का तरीका ढूंढ लिया है। डीलर गेहूं वितरण के दौरान राशनकार्ड धारक का अंगूठा लगाकर गेहूं को वितरण कर देते हैं तथा केरोसीन नहीं देते हैं। इस केरोसिन को कालाबाजारी में बेचते है और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें लम्बे समय से केरोसीन नहीं मिला हैं जिससे उनको परेशानी होती हैं जिसके बारे में कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। हांलाकि साइट ऑनलाइन केरोसीन वितरित होना बताया जा रहा है।

धमकी देकर शिकायत वापस लेने का बनाया दबाव

ऑनलाइन शिकायत करने के बाद से ही राशन डीलर शिवराज व पुरषोतम उपाध्याय ने मुझे फोन कर के शिकायत वापस लेने व राजीनामा लिखकर देने का दबाव बनाया और मेरे नाम से एक पेपर पर शिकायत के जवाब में झूठा और फर्जी माफीनामा बना कर अधिकारियों को भेज दिया और जांच के लिए आए अधिकारी ने मेरे से बिना मिले खानापूर्ति कर के रिपोर्ट डीलर के पक्ष में बना दी

- बबलू प्रजापत, शिकायतकर्ता।

भूलवश हो गया होगा उसे केरोसिन दे दिया जाएगा

यह जानबुझ कर नहीं किया गया हैं। भूलवश हो गया होगा। मैंने शिकायतकर्ता बबलू प्रजापत से बात करके बोला भी था की ये जानबूझकर नहीं किया हैं। मैं उसे गलती से उठाया गया केरासिन वापस देने के लिए तैयार हू। और मैने फोन पर धमकी नहीं दी थी वर्ष 2019 से ये मेरा उपभोक्ता हैं इससे पहले ये पुरुषोतम उपाध्याय का उपभोक्ता था।

- शिवराज पालीवाल, राशन डीलर खींवसर

शिकायत मिलते ही दोषी पर कार्रवाई करते हैं

ऐसा कोई मामला हमारे पास आया नही हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो में कल ही इसकी पूरी जांच करवा लेता हूं। जिले में ऐसा कोई मामला आता है तो तुरंत जांच कर उचित कार्यवाही की जाती है। और जांच में अगर राशन डीलर दोषी पाया जाता है। तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

- पार्थ सारथी, जिला रसद अधिकारी, नागौर

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-दैनिक भास्कर,नागौर	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन,रसद विभाग,नागौर	संबन्धित मामला:-हेराफेरी,धमकी

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय की महाप्रबंधक ने टेण्डर निरस्त कर पुन: कराने के दिए निर्देश

जो फर्म तीन साल के लिए ब्लैक लिस्टेड, अब उसी का टेण्डर स्वीकार

समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन हैण्डलिंग एवं परिवहन का टेण्डर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

एक्सक्लूसिव

भरतपुर/नदबई. जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद के लिए हैण्डलिंग व परिवहन की टेण्डर प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। उप रजिस्ट्रार कार्यालय ने ऐसी ही फर्म का तकनीकी रूप से टेण्डर आवेदन स्वीकार कर लिया जो पूर्व में करौली जिले से तीन साल के लिए ब्लैक लिस्टेड हैं। विशेष बात ये है कि इसके बाद भी उक्त फर्म करीब एक साल से जिले में नदबई, बयाना, वैर व कामां क्षेत्र के एमडीएम के परिवहन कार्य कर रही है। यह मामला उस समय सामने आया, जब जिले के नदबई क्षेत्र के गांव रायसीस निवासी ठेकेदार वीरेन्द्र सिंह ने उक्त फर्म के ब्लैक लिस्ट फर्म होने के बावजूद अपने चहेते को टेण्डर देने का आरोप लगाते जिला कलक्टर समेत विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है। उधर, शिकायत होने पर राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय की महाप्रबंधक ने उप रजिस्ट्रार को मामले की जांच करने और निविदा प्रक्रिया तुरंत निरस्त कर नई निविदा जारी करने के निर्देश दिए हैं।

गड़बड़ी के खेल में छिपी है बड़ी कहानी

सूत्रों के अनुसार जिला मुख्यालय पर हैण्डलिंग व परिवहन के लिए 20 मार्च को टेण्डर होना था। इसको अज्ञात कारण के चलते विभागीय अधिकारियों ने निरस्त कर दिया। इसके बाद में 21 अप्रेल को अधिकारियों ने ब्लैक लिस्ट फर्म की बिड स्वीकार कर ली। आवेदन स्वीकार करने पर अन्य ठेकेदार ने मामले में विभागीय अधिकारी समेत प्रबंधक निदेशक राजफैड, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता, सहकारिता मंत्री समेत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उपरजिस्ट्रार पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए शिकायत की की है।

जहां कार्यरत रहे, वहां उक्त फर्म को दिया कार्य

शिकायतकर्ता आरोप है कि उक्त फर्म उपरजिस्ट्रार के रिश्तेदार की फर्म है। उपरजिस्ट्रार राजीव लोचन की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2019 को हुई बैठक में पंचायत समिति नदबई के एमडीएम परिवहन का कार्य फर्म मैसर्स गिरजेश ट्रेडर्स बयाना को दिया गया। आरोप है कि उपरजिस्ट्रार पांच केवीएसएस के प्रशासक रहे। उस दौरान भी उक्त फर्म को कार्य दिया गया। नदबई के अलावा वैर, बयाना, कामां को भी ठेका दिया गया।

इसलिए ब्लैक लिस्ट की गई फर्म

फर्म मैसर्स गिरजेश ट्रेडर्स बयाना ने राजफैड करौली को गत 12 अक्टूबर 2017 को पत्र लिखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का खाद्यान्न का उठाव करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए पीडीएस का गेहूं उठाने से मना कर दिया था। विभाग ने उक्त फर्म की ओर से करार को भंग करने का दोषी माना। करौली जिला उपापन समिति के निर्णय के तहत उक्त फर्म की समस्त प्रतिभूति राशि 7 लाख 51 हजार 36 6 को जब्त करते हुए तीन साल के लिए फर्म को विवर्जित (ब्लैक लिस्टेड) किया गया था।

नियमानुसार प्रदेश सरकार किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट करती तो सभी जगह प्रभावित होती। उक्त फर्म को करौली खाद्य व आपूर्ति निगम लि. ने ब्लैक लिस्ट किया है। इसलिए यह फर्म अन्य जिले में कार्य कर सकती है। मिलीभगत जैसा कोई मामला नहीं है। उक्त फर्म ने खाद्य निगम में भी अक्टूबर 18 तक कार्य किया है।

राजीव लोचन शर्मा, उपरजिस्ट्रार सहकारी समिति भरतपुर

उक्त मामले में शिकायत मिलने पर उपरजिस्ट्रार को मामले की जांच करने एवं ब्लैकलिस्टेड फर्म होने पर टेण्डर निरस्त करते हुए वापस टेण्डर कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रीति शर्मा, महाप्रबंधक राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय

09 संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-राजस्थान पत्रिका,भरतपुर	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-राज. राज्य सहकारी क्रय विक्रय	संबन्धित मामला:-भ्रष्टाचार

10

क भास्कर के खुलासे के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा #राजस्थान_ LDC_घोटाला, 1.60 लाख दा ट्वीट करके मांगा न्याय, सांसद किरोड़ीलाल मीणा व हनुमान बेनीवाल ने भी की जांच की मांग

एलडीसी भर्ती : कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक उठा चुके हैं सवाल, फिर भी जांच नहीं कर रहे अधिकारी

भास्कर संवाददाता | सीकर

राजस्थान में एलडीसी-2018 भर्ती में 587 पदों में गड़बड़ी के मामले को अफसर दबाने की कोशिश में जुटे हैं। हैरानी यह है कि एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद और 16 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग कर चुके हैं और पद बढ़ाने की मांग रख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कैबिनेट मंत्री व विधायकों के पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। दैनिक भास्कर के पास इन सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के पत्र हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पद घटाना ओबीसी व सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ है। इसी तरह वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने भी सीएम को पत्र लिखकर पद बढ़ाने की मांग की। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से युवाओं में अविश्वास व रोष पनप रहा है। सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी पद कटौती कर की गई गड़बड़ी की जांच की मांग कर चुके हैं। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया। पूरे भारत में हैशटैग #राजस्थान_ LDC_घोटाला के साथ 1.60 लाख से ज्यादा ट्वीट किए। इन ट्वीट के साथ भास्कर की खबर भी ट्रेंड कर रही थी। राजस्थान में यह ट्वीट दूसरे नंबर पर रहा। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री गहलोत को भास्कर की खबर ट्वीट करके आरक्षण में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि ओबीसी व सामान्य वर्ग के 587 पद वापस जोड़े जाने चाहिए।

एलडीसी भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को भी अभी तक नियुक्ति नहीं

ट्विटर कैंपेन में दैनिक भास्कर की खबर ट्रेंड करती रही।

एलडीसी भर्ती 2018 के रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ नहीं हो पा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार चाहे तो गड़बड़ी के मामले की जांच जल्द कराकर नियुक्ति जल्द कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों को अगर नियुक्ति अभी दे दी जाए तो भी पद बढ़ाने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अभ्यर्थियों ने भी रविवार को ट्विटर पर कैंपेन चलाकर नियुक्ति की मांग की। इन्होंने 2.50 लाख से ज्यादा ट्वीट किए।

इन्होंने लिखे हैं पत्र : नवलगढ़ विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, डीडवाना विधायक चेतन डूडी, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, बूंदी विधायक अशोक डोगरा, भादरा विधायक बलवान पूनिया, तिजारा विधायक संदीप यादव, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र कुमार, सरदारशहर विधायक भंवरलाल शर्मा आदि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग कर चुके हैं।

लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए : उपेन यादव

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश संयोजक उपेन यादव का कहना है कि लॉक डाउन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर कम किए गए पदों को वापस जुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण में छेड़छाड़ करके 587 पद खत्म करना गलत है। मामले को लेकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-दैनिक भास्कर,नागौर	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-राजस्थान सरकार	संबन्धित मामला:-बेरोजगारी,भ्रष्टाचार

11

वर्षाजल संग्रहण में बाधक बन सकती है तालाब की खुदाई

तालाब खोद कर अवैध रूप से निकाल रहे मिट्टी

रामसीन @ पत्रिका. निकटवर्ती मुड़तारा के देवजी तालाब से अवैध रूप से खुदाई कर मिट्टी निकाली जा रही है। मिट्टी निकालने के लिए तालाब में कुछ जगह तो इतनी गहरी खुदाई कर दी गई है कि मुरड़ तक दिखाई देने लगा है। ऐसे में यदि इस स्थान पर समय रहते फिर से मिट्टी नहीं डाली गई तो बारिश में संग्रहित होने वाला पानी रिसकर बहने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि इस तालाब को गहरा करने के लिए अधिकारिक तौर पर इस बार गाद निकालने का काम नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने अवैध रूप से तालाब में खुदाई कर दी। विशेषज्ञों का मानना है कि तालाब के तल की मिट्टी हमेशा जल संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी मिट्टी के कारण लंबे समय तक तालाब में पानी भरा रहता है।

यदि गहरा करने के लिए ज्यादा मात्रा में मिट्टी निकाली जाती है और नीचे मुरम या मुरड़ आ जाती है तो यह तालाब के लिए खतरे का संकेत है। अगर इस जगह पर दोबारा मिट्टी नहीं डाली गई तो बारिश के दौरान भले ही तालाब लबालब भर जाए, लेकिन वह तेजी से खाली भी हो जाएगा। कुएं और बावड़ियों को लंबे समय तक जीवित रखने में तालाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तालाबों में पानी भरा रहने से ही जल स्रोतों में भूमिगत आवक बनी रहती है।

जवाब दे रहे नलकूप

कस्बे में फिलहाल पानी का संकट चल रहा है। ऐसे में तालाब में पानी पर्याप्त रहेगा तो कस्बे के सैकड़ों नलकूपों में पानी की उपलब्धता भी बनी रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में मुरम वाली जगह पर मिट्टी नहीं डाली गई तो निश्चित रूप से वहां से पानी का रिसाव होगा और भविष्य में पेयजल संकट के हालात बनेंगे।

मानसून के पहले देना होगा ध्यान

मुड़तरा सिली गांव के देवजी तालाब सहित अन्य तालाबों पर भी ग्राम पंचायतों को मानसून आने से पहल ध्यान देना होगा। अक्सर तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण के कारण पानी की आवक नहीं हो पाती है। ऐसे में ग्रामीणों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसको लेकर अभी से देवजी तालाब सहित अन्य तालाबों के कैचमेंट एरिया पर भी ध्यान दिया जाए तो भविष्य में परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा तालाबों तक पहुंचने वाले छोटे-बड़े नालों और अन्य आवक वाले स्थान पर भी सुधार कार्य की जरूरत है।

इनका कहना है

मुड़तरा सिली के तालाब में अगर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- मेहराराम जाट, नायब तहसीलदार रामसीन

संबन्धित समाचार पत्र एवं संस्करण:-राजस्थान पत्रिका,जालोर	प्रकाशन दिनांक:-27/04/2020
जिम्मेदार विभाग:-जिला प्रशासन,जालोर	संबन्धित मामला:-अवैध खुदाई

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,वैशालीनगर,302012 मोबाइल:-9828346151